एच एस बी

लैटर्स पेटेंट अपील

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, सुरिंदर सिंह के समक्ष

रीखी राम और अन्य – आवेदनकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य – उत्तरदाता

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1974 की 178
29 अक्टूबर 1975

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का X)-धारा 3-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 19(1)(जी)-हरियाणा गेहूं (उत्पादकों द्वारा स्टॉक पर प्रतिबंध) आदेश 1973-क्या अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है।

यह अभिनिर्धारित गया कि केवल इसलिए कि हरियाणा गेहूं (उत्पादकों द्वारा स्टॉक पर प्रतिबंध) आदेश 1973 के अनुपालन में, उत्पादक को निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं के अपने सभी स्टॉक को कम समय और निरंतर के भीतर सरकार को निपटाने के लिए कहा जाता है। डीलरों को पूरे वर्ष अपना व्यापार प्रभावी ढंग से चलाने के लिए स्टॉक का प्रवाह उपलब्ध नहीं होगा, भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 19(1)(जी) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। व्यापारियों की यह आशंका कि गेहूं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें व्यापार से हटा दिया जाएगा और एक समय में उनके पास गेहूं की अधिकतम सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, पूरी तरह से गलत है। व्यापारी हमेशा अन्य डीलरों से गेहूं खरीदकर अपने स्टॉक को दोबारा बढ़ा सकते हैं। अपना व्यापार चलाने के लिए गेहूं का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग भी अनुचित है। संवैधानिक गारंटी केवल एक नागरिक के व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार की रक्षा कर सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी उपलब्ध नहीं है कि नागरिक को पूरे वर्ष उसके व्यापार या व्यवसाय में कोई लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मौसम, उत्पादन, आर्थिक स्थितियों और कई अन्य कारकों में उतार-चढ़ाव हमेशा एक व्यापार या व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है और यह ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि क्या यह उसके लिए लाभदायक है या नहीं और क्या वह चाहेगा उक्त व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के लिए। राज्य इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दे सकता। अनुच्छेद 19(6) के तहत परिकल्पित "उचित प्रतिबंध" कुछ वस्तुओं के मामले में, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हैं, पूर्ण निषेध तक भी बढ़ाया जा सकता है। स्टॉक ऑर्डर पूर्ण पदोन्नति के चरण के करीब भी नहीं है, बल्कि केवल नियामक है, इस प्रकार हरियाणा गेहूं (उत्पादकों द्वारा स्टॉक पर प्रतिबंध) आदेश 1973 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं है।

(पैरा 10 और 11)

लेटर्स पेटेंट माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा के 13 फरवरी, 1974 के सिविल रिट संख्या 2570, 1973 में पारित फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील।

याचिकाकर्ताओं के वकील जी. आर. मजीठिया।
भारत संघ के वकील, कुलदीप सिंह।
नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी, महाधिवक्ता हरियाणा के लिए।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह – (1) रिखी राम और अन्य ने (1) रिखी राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील की है। उक्त रिट याचिका के संबंध में तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(2) अपीलकर्ता 1 से 10 चक्की-मालिक हैं, जो कालका (हरियाणा राज्य) में गेहूं पीसने का व्यवसाय करते हैं। कहा जाता है कि अपीलकर्ता 11 और 12 गेहूं पीसने का काम करने वाले व्यापारी हैं। अपीलकर्ता हरियाणा गेहूं डीलर लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973 (संक्षेप में, मूल्य नियंत्रण आदेश) के तहत फॉर्म 'बी' में लाइसेंस धारक होने का दावा करते हैं, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुबंध 'ए' में है। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से दाखिल रिटर्न में यह रुख अपनाया गया है कि अपीलकर्ताओं नंबर 11 और 12 ने उपरोक्त आदेश के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। रिट याचिका में ऊपर उल्लिखित मूल्य नियंत्रण आदेश के अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए कुछ आदेशों का विस्तृत संदर्भ दिया गया था। - पहला इंटर-जोनल गेहूं और सफेद उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 (संक्षिप्तता के लिए, संचलन नियंत्रण आदेश) है, जो केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 1973 को जारी किया गया था, और अप्रैल के हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 24, 1973, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुबंध 'बी' में है। मूल आंदोलन नियंत्रण आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रों का गठन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा राज्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 2 अप्रैल, 1973 को जारी एक संशोधन के अनुसार, इस राज्य को सूची में शामिल किया गया था। संशोधित आदेश की एक प्रति भी रिकॉर्ड में है। रिट याचिका में संदर्भित तीसरा आदेश हरियाणा गेहूं (उत्पादकों द्वारा स्टॉक पर प्रतिबंध) आदेश, 1973 (इसके बाद स्टॉक ऑर्डर है) है, जिसकी प्रतिलिपि रिट याचिका के अनुबंध 'सी' में है। यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा 20 जून, 1973 को अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जो कि हरियाणा सरकार को इन मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के साथ कानून बनाने में सक्षम बनाने वाले आदेशों के साथ पढ़ा गया था। रिट याचिका के मुख्य भाग में, हरियाणा गेहूं डायलर्स लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973 के तहत जारी 26 जून, 1973 की एक और गैर-स्थानीय वस्तु की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था, जिसकी प्रतिलिपि रिट याचिका के अनुबंध 'डी' में है। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका के समापन पर की गई प्रार्थना में इस चुनौती को कम कर दिया गया है, हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश, जो वर्तमान अपील में लगाया गया है, इंगित करता है कि जब मामला उस न्यायालय के समक्ष प्रचारित किया गया था, तो वैधता उपर्युक्त सभी आदेशों पर विचार किया गया।

(3) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जिन विभिन्न बिंदुओं पर आग्रह किया गया था, उन्हें फैसले में विशेष रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है: -

1. गेहूं की कीमत मनमाने आंकड़े पर तय की गई है. गेहूं का बाजार मूल्य बहुत अधिक है और व्यापारियों, विशेषकर चक्की मालिकों को कोई लाभ नहीं होता है। कीमत के इस मनमाने निर्धारण ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) (एफ) और (जी) के तहत उन्हें मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।
2. जिन क्षेत्रों में सामान्यतः गेहूँ का उत्पादन होता है तथा जिन क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन लगभग नगण्य मात्रा में होता है, उन क्षेत्रों के लिए गेहूँ की कोई एक समान कीमत तय नहीं की जा सकती।

3. राज्य सरकार कीमतों का निर्धारण तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह चक्की मालिकों की तरह व्यापारियों को गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित न कर दे।

(4) पुनः बिंदु (1) जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विस्तार से विचार किया गया, संक्षेप में बोलते हुए, यह माना गया कि यह मानने का कोई आधार नहीं था कि सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की कीमत मनमानी थी। उत्तरदाताओं के पक्ष को स्वीकार करते हुए यह भी माना गया कि सरकार ने स्वयं साधारण गेहूं रुपये की दर से खरीदा था। 76 रुपये प्रति क्विंटल और चक्की मालिकों और अन्य व्यापारियों को इसे रुपये की दर से बेचने की अनुमति दी गई। 83.50 प्रति क्विंटल से पता चलता है कि व्यापारियों के लिए काफी मार्जिन बचा हुआ था। रुपये का अतिरिक्त मार्जिन. चक्की मालिकों को गेहूँ पीसकर आटा बनाने पर 6 रूपये प्रति क्विंटल की छूट दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी अपीलकर्ताओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनमें से कोई भी गेहूं की वास्तविक उपज नहीं थी और इसलिए यह उनके लिए खुला नहीं था कि वे यह कहें कि जिस कीमत पर उत्पादक को गेहूं बेचने के लिए कहा गया था वह नहीं था। उचित मूल्य. इस संबंध में एक अवलोकन किया गया था कि जाहिर तौर पर अपीलकर्ता वास्तविक उत्पादकों के हित की वकालत कर रहे थे ताकि वे अप्रत्यक्ष रूप से गेहूं की अप्रतिबंधित जमाखोरी और अनियंत्रित कीमतों पर इसकी बिक्री के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से वास्तविक लाभ उठा सकें।

(5) बिंदु (2) और (3) के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि राज्य सरकार राज्य में घाटे वाले क्षेत्रों की जरूरतों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक निश्चित दर पर गेहूं खरीद रही है, इसलिए इसका निर्धारण गेहूं के लिए समान दरें--क्रय क्षेत्र और गैर-क्रय क्षेत्र को किसी भी वैध हमले का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह भी माना गया कि यदि कोई आवश्यक वस्तु कम आपूर्ति में है, तो स्थिति को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिन कदमों पर हमला करते हैं, वे तब तक खुले नहीं होते जब तक कि नागरिकों के किसी भी ठोस अधिकार का उल्लंघन न हो और इसलिए कोई व्यापारी तय करने से पहले इस पर जोर नहीं दे सकता। सरकार को उन्हें एक निश्चित मात्रा में गेहूं की आपूर्ति करने के लिए न्यूनतम या अधिकतम कीमतों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए, दोनों विवाद निरस्त कर दिए गए। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश, यानी, मूल्य नियंत्रण आदेश और स्टॉक ऑर्डर, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हैं; याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं को गारंटी। केंद्र सरकार के आदेश दिनांक 31 मार्च, 1973, यानी, आवागमन नियंत्रण आदेश, की भी प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में जांच की गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस आदेश के प्रावधान किसी भी तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे देखा कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में इस आदेश के तहत परमिट के लिए आवेदन किया था और उन्हें ऐसा परमिट देने से इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार, वे आदेश की वैधता पर सवाल उठाने में सक्षम नहीं थे। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी गई।

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर आपत्ति करने की दृष्टि से, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जी.आर. मजीठिया ने अपने संबोधन के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया:-

> (i) स्टॉक ऑर्डर जो एक उत्पादक के पास गेहूं की अधिकतम मात्रा के संबंध में प्रतिबंध लगाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) का उल्लंघन है क्योंकि उक्त आदेश अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार को प्रभावित करता है।
>
> (ii) संचलन नियंत्रण आदेश, जो बिना परमिट प्राप्त किए आंचलिक सीमा क्षेत्र के किसी स्थान से/उस क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान तक गेहूं की आवाजाही पर मनमाना प्रतिबंध लगाता

है, अपीलकर्ताओं के उपलब्ध मौलिक अधिकार का हनन करता है। उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत।

(iii) 26 जून 1973 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया मूल्य नियंत्रण आदेश मनमाना है और अधिनियम की धारा 3 के दायरे से बाहर है क्योंकि इसमें डीलर के लिए लाभ का कोई उचित मार्जिन नहीं बचा है और यह बदले में समाप्त करने के समान है। अपीलकर्ता अपने व्यापार से। इसलिए, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है।

(7) बिंदु (i) को लेने से पहले बिंदु (ii) और (iii) को लेना बेहतर हो सकता है क्योंकि इसके बाद देखी गई परिस्थितियों को देखते हुए इन बिंदुओं को बिना किसी कठिनाई के निपटाया जा सकता है।

(8) बिंदु (ii) के संबंध में, जो आवागमन नियंत्रण आदेश की वैधता के खिलाफ चुनौती से संबंधित है, यह विवादित नहीं है कि किसी भी अपीलकर्ता ने परमिट देने के लिए किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया था। ऐसे किसी अनुरोध के अभाव में परमिट देने या अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन तथ्यों का आवश्यक परिणाम यह है कि आवश्यक परमिट के लिए आवेदन किए बिना, अपीलकर्ताओं के पास आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान वकील ने इस बिंदु पर जोर नहीं दिया, और यह सही भी है, और यह भी प्रस्तुत किया कि यदि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किए जाने पर परमिट देने के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं और यह अस्वीकृति प्रतिकूल होगी उनके अधिकारों को प्रभावित करें, वे इस संबंध में एक आधार बनाएंगे। बार में विद्वान वकील के बयान के मद्देनजर, इस बिंदु पर आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।

(9) अब बिंदु (iii) पर आते हैं, जो मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत जारी 26 जून 1973 की अधिसूचना की मनमानी प्रकृति के खिलाफ एक चुनौती से संबंधित है, विद्वान जिला अटॉर्नी, हरियाणा द्वारा विवाद को सोल्व कर दिया गया है। हमारे नोटिस में, अधिसूचना संख्या एस.ओ. के आधार पर। 64/एच.डब्ल्यू.डी.एल./पी.सी^ओ|;7 73/सी1. 13/74, दिनांक 29 अप्रैल 1974, पूर्व अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 221/एच.डब्ल्यू.डी.एल. एवं पी.सी.ओ./73/सी1. 13/73, दिनांक 16 नवम्बर 1973 को रद्द कर दिया गया। 16 नवंबर, 1973 की अधिसूचना वही थी जिसने 26 जून, 1973 की विवादित अधिसूचना को हटा दिया था, जिसके अनुसार गेहूं और गेहूं के आटे का बिक्री मूल्य तय किया गया था। इसलिए, 29 अप्रैल 1974 की अधिसूचना का प्रभाव यह है कि गेहूं या गेहूं के आटे की बिक्री के लिए कोई बिक्री मूल्य निर्धारित नहीं है। इसलिए, डीलर के लिए लाभ का उचित मार्जिन तय करने का सवाल ही नहीं उठता और इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए हमले का यह आधार अब उपलब्ध नहीं है। इस कारण से अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस विवाद पर जोर नहीं दिया है।

(10) किरण को अब बिंदु (i) पर केंद्रित किया जा सकता है। इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि स्टॉक ऑर्डर में गेहूं की अधिकतम मात्रा के लिए एक सीमा निर्धारित की गई थी जो एक उत्पादक अपने और अपने घर के उपयोग के लिए, उसके लिए आवश्यक गेहूं की मात्रा के अलावा रख सकता है। बीज के रूप में उपयोग के लिए स्टॉक ऑर्डर में आगे निर्देश दिया गया कि इस आदेश के शुरू होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर उत्पादक को अपने कब्जे में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा राज्य सरकार को 13 अप्रैल, 1973 को जारी अधिसूचना के तहत पहले से तय खरीद कीमतों पर देनी होगी। मूल्य नियंत्रण आदेश के खंड 6(1) के तहत। तर्क यह है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, उत्पादक को निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं के अपने सभी स्टॉक को कम समय के भीतर

सरकार को निपटाने के लिए कहा जाता है और स्टॉक का निरंतर प्रवाह उपलब्ध नहीं होगा। डीलरों को पूरे वर्ष अपना व्यापार प्रभावी ढंग से चलाने के लिए। तर्क के इस तरीके से अनुच्छेद 19(1)(जी) के कथित उल्लंघन को दबाने की कोशिश की जाती है। इस विवाद के लिए समर्थन मांगने की दृष्टि से, विद्वान वकील इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच (एस.एस. संधावालिया और के.एस. तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति) द्वारा (प्रताप सिंह केडियन बनाम द स्टेट ओ) पंजाब, आदि (2) के अंशों का हवाला देते हुए परेशान हो रहे हैं। उक्त मामले में विवादित आदेश पंजाब गेहूं (उत्पादकों द्वारा स्टॉक पर प्रतिबंध) आदेश, 1974 था, जिसे अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे और दायरे से परे माना गया था और इसलिए, शून्य था। यह तर्क दिया गया है कि उस मामले में देखे गए कारणों से, हरियाणा स्टॉक ऑर्डर को भी रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, यह तर्क विभिन्न कारणों से मान्य नहीं है। वर्तमान एक लेटर्स पेटेंट अपील है। जिस बिंदु पर अब अपील में बहस की जा रही है, वह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था और अपीलकर्ताओं को इस स्तर पर पहली बार इस मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरे, अपीलकर्ताओं के पास उस मामले में निर्माताओं के पक्ष की पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है, जहां बाद वाला वर्ग एक पक्ष भी नहीं है। स्टॉक ऑर्डर से अपीलकर्ताओं का कोई भी कानूनी अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होता है और उक्त आदेश का दूरगामी परिणाम, जो कि भ्रामक है, अपीलकर्ताओं को आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं दे सकता है।

(11) अपीलकर्ताओं की यह आशंका कि गेहूं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें उनके व्यापार से हटा दिया जाएगा और एक समय में उनके पास गेहूं की अधिकतम सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, मूल्य नियंत्रण आदेश के रूप में भी गलत है। 1973 को 31 मार्च 1975 की अधिसूचना द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से, आदेश के खंड 5 के उप-खंड (3) को, जैसा कि यह मूल रूप से था, हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को गेहूं बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता हमेशा अन्य डीलरों से गेहूं खरीदकर अपने स्टॉक को फिर से भर सकते हैं। अपीलकर्ताओं की यह मांग कि उनके व्यापार को चलाने के लिए गेहूं का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कम से कम, काफी अनुचित है। संवैधानिक गारंटी केवल किसी नागरिक के व्यापार या व्यवसाय चलाने के अधिकार की रक्षा कर सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी उपलब्ध नहीं है कि नागरिक को पूरे वर्ष उसके व्यापार या व्यवसाय में कोई लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मौसम में उतार-चढ़ाव, उत्पादन, आर्थिक स्थिति और कई अन्य कारक हमेशा किसी व्यापार या व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं और यह ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसके लिए लाभदायक है या नहीं और क्या वह ऐसा करेगा। उक्त व्यापार या व्यवसाय को जारी रखना चाहते हैं। राज्य इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे. अनुच्छेद 19(6) के तहत परिकल्पित "उचित प्रतिबंध", कुछ वस्तुओं के मामले में, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हैं, पूर्ण निषेध तक विस्तारित हो सकता है (मध्य भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड, बनाम भारत संघ और अन्य) (3). विवादित आदेश पूर्ण प्रतिबंध के स्तर के करीब भी नहीं हैं, बल्कि केवल नियामक हैं।

(12) प्रताप सिंह रेडियन के मामले (सुप्रा) में निर्णय एक निर्माता द्वारा दायर रिट याचिका में दिया गया था, न कि किसी व्यापारी द्वारा। इस मामले में भी विद्वान न्यायाधीशों के पास यह देखने का अवसर था कि किसान या कृषि उत्पादक स्पष्ट रूप से व्यापारी या डीलर से भिन्न स्तर पर है, जो अन्य स्रोतों से उपज प्राप्त या खरीद सकता है। आगे यह देखा गया कि उनके मामले में, किसी विशिष्ट स्थिति में शायद यह उचित हो सकता है कि वे किसी विशिष्ट स्टॉक या सीमा से अधिक खरीदारी, अधिग्रहण या भंडारण नहीं करेंगे। पंजाब मामले में स्टॉक ऑर्डर के संबंध में स्थिति भी वर्तमान मामले में स्टॉक ऑर्डर से अलग थी। पंजाब स्टॉक ऑर्डर के खंड 5 के तहत उत्पादक को अपने कब्जे में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का निपटान

करना आवश्यक था लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसे इसे बेचा जाना था। इसलिए, एक तर्क दिया गया कि यह आदेश ख़राब था क्योंकि अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष खरीदार निर्धारित नहीं किया गया था। विवादित हरियाणा स्टॉक ऑर्डर में, उत्पादक को गेहूं का अपना अतिरिक्त स्टॉक सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए सरकार को निर्धारित खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। इसलिए, यह तर्क कि उत्पादक गेहूं के अपने अतिरिक्त स्टॉक को औने-पौने दाम पर छोड़ने के लिए बाध्य होंगे, हरियाणा स्टॉक ऑर्डर के मामले में उपलब्ध नहीं है। इस और अन्य विभेदक विशेषताओं के कारण, प्रताप सिंह रेडियन का मामला (सुप्रा) अपीलकर्ताओं के मामले में कोई सहायता नहीं करता है। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि (मैसर्स धन्ना माई सहई राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य) (4) में कुछ डीलरों की ओर से दायर मामले में, उसी डिवीजन बेंच ने गेहूं डीलर लाइसेंसिंग को रद्द करने से इनकार कर दिया था। और मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1974, जिसके द्वारा पंजाब के थोक डीलरों को एक निश्चित सीमा से अधिक गेहूं के अपने सभी स्टॉक को एक निश्चित मूल्य पर सरकार को बेचने की आवश्यकता थी और यहां तक कि उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। गेहूँ केवल उपभोक्ताओं को बेचें, किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त डीलर को नहीं।
(13) प्रताप सिंह कादियान, जो अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्कों का मुख्य मुद्दा था, शायद ही इससे अधिक कुछ हो सकता था और अपील के समर्थन में आग्रह किया गया था जो विफल हो जाता है और इसे हर्ज़े के साथ खारिज कर किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़